पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21
RNI-MPHIN/2015/72544
साप्ताहिक
चौपाल से भोपाल तक

जागत गांव हमार

भोपाल, सोमवार, 01 फरवरी 2021, वर्ष-6, अंक-44
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

विंध्य के जुनून और जज्बे को मिली पहचान, शिवराज ने नवाजा

- सम्मानित होने के बाद बोले धर्मजय, यहां तक पहुंचाने में **जागत गांव हमार** का बड़ा योगदान
- पीएम नरेंद्र मोदी के सपने और प्रदेश सरकार के आत्मनिर्भर मप्र को साकार करने में जुटे विंध्य के धर्मजय सिंह

संवाददाता, भोपाल

जैविक खेती में देश में पहले मुकाम पर मध्यप्रदेश का किसान भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में कई किसान अपने जुनून और जज्बे से बंजर भूमि पर सोना उगा रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं विंध्य के धर्मजय सिंह। अपनी मेहनत और लगन के बूते सपने को साकार करने में जुटे रीवा के प्रगतिशील किसान धर्मजय ने न सिर्फ विंध्य, बल्कि मप्र का मान बढ़ाया है। पिछले दिनों 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को उन्हें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों सम्मानित किया। सम्मानित होने के बाद गौरवान्वित धर्मजय सिंह ने इस सम्मान के लिए जागत गांव हमार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वह तो लंबे समय से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की

दिशा में आत्मनिर्भर किसान बनने का सपना सजोने में जुटे थे, लेकिन उन्हें **जागत गांव हमार** ने न सिर्फ पहचान दिलाई, बल्कि उनके जुनून और जज्बे को मंजिल तक पहुंचाने का मंच प्रदान कर बड़ी भूमिका निभाई है।

जागत गांव हमार इम्पैक्टः
इस खबर ने दिलाया विंध्य को सम्मान

सपना कर रहा साकार

सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों सम्मानित होने वाले धर्मजय सिंह को प्रगतिशील किसान का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। सम्मानित होने के बाद धर्मजय सिंह ने कहा कि, किसान का बेटा हूं खेती करना मेरा धर्म है। अपने साथ दूसरों के पेट भरना मेरा धर्म है। मैं इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर मप्र का सपना साकार कर रहा हूं।

आत्मनिर्भर अन्नदाता

जागत गांव हमारे ने18 जनवरी 2021) में '**फल की खेती में फायदा**' नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसमें रीवा के प्रगतिशील किसान धर्मजय सिंह की स्ट्रॉबेरी की फसल को प्रमुखता से प्रकाशित की थी। वे बंजर भूमि पर स्ट्रॉबेरी की फसल उगाकर खेती को फायदे का जरिया बनाकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं।

अफसर पहुंचे गांव

खबर प्रकाशित होने के बाद कृषि विभाग और प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए न सिर्फ धर्मजय सिंह के गृह ग्राम रकरी पहुंची, इस दौरान उनकी फसल का निरीक्षण भी किया। अपने खेत में अपनों के बीच कृषि विभाग और प्रशासनिक अमला को देख धर्मजय सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

शिवराज बोलेः बिना लिए-दिए समय पर कार्य हो, यही सुशासन

अब फोन पर खसरा खतौनी-नक्शे की नकल

- बेहतर काम वाले होंगे पुरस्कृत, नहीं करने वालों पर गिरेगी गाज
- सेवा न मिलने पर स्वतःजनित होकर आवेदक को मिलेगी सेवा

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश के किसानों के साथ ही आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सराहनीय पहल की है। साथ ही सीएम हेल्प लाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल पर खसरा, खतौनी और नक्शा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रारंभी की है। जो अधिकारी-कर्मचारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो नहीं करेंगे, उन पर सरकार की गाज गिरेगी। जनप्रतिनिधियों साथ ही अफसर भी समय सीमा में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की वे सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करें। अब सीएम हेल्प लाइन 181 में फोन पर ही सेवा यानी आने जाने का चक्कर खत्म। सीएम डैशबोर्ड पर हर जानकारी मुख्यमंत्री के सामने रहेगी। हर योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। नागरिकों को कंप्यूटर से सरकारी सेवाएं व सुविधाएं मिल जाएं, यह सरकार की सोच है। सरकारी तंत्र में टेक्नॉलाजी का उपयोग कर जनता की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए एमपी इनोवेशन पोर्टल तैयार किया गया है।

ऐसे मिलेगा सुविधा का लाभ

मध्यप्रदेश के किसानों और संबंधितों को केवल एक फोन सीएम हेल्प लाइन के 181 पर फोन लगाने पर इस सुविधा का लाभ मिल जाएगा। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आधार और मोबाइल नंबर पंजीकृत होना जरूरी है। जैसे ही इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित द्वारा 181 पर फोन किया जाएगा।

नई डीम्ड सेवाएं

नई सुविधाओं सीएम जनसेवा, सीएम डैशबोर्ड पोर्टल, वाट्सएप चैटबॉट सुविधा और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन से मान्य अनुमोदन श्रेणी को जोड़ने का नवाचार शुरू किया गया है। सुशासन के क्षेत्र में मान्य अनुमोदन श्रेणी की चार नई सेवाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

नागरिकों को दफ्तरों में बिना लिए-दिए और बिना चक्कर लगाए तय समय-सीमा में सेवा प्राप्त हो, यही सुशासन है। मप्र से अन्य राज्य भी प्रेरणा लेकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में सीएम सेवा 181 के माध्यम से फोन द्वारा ही सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं। इसका विस्तार करते हुए अब तीन और सर्वाधिक जन-उपयोगी सेवाएं खसरा, खतौनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि सीएम जनसेवा के माध्यम से प्रदाय की जाएगी।
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

देश के 24 राज्यों ने मध्यप्रदेश को आदर्श मानकर लोक प्रबंधन विभाग का गठन किया है। दस वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में लोक सेवा और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई। जनता को परेशान करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पब्लिक सर्विस डिलेवरी गारंटी कानून बनाया गया है। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से अब एक नया माध्यम आमजन को उपलब्ध होगा।
अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री

हरदा में प्रदेश की पहली फसल ओपीडी

- » मध्यप्रदेश में किसानों के खेत सड़ रहे हों तो न लें टेंशन
- » अब फसल ओपीडी में फोन पर ही हो जाएगा उपचार

संवाददाता, भोपाल

यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच है। अब मप्र के किसानों की फसल के लिए प्रदेश में ओपीडी खोल दी गई है। अगर किसानों की फसल सड़ रही है या खराब हो रही है तो उन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन नंबरों 9009801134, 9425637728, 9424492520 पर वॉटसऐप करना है। दरअसल, मप्र सरकार ने खराब होने वाले फसलों के इलाज के लिए फसल ओपीडी खोलने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले हरदा से की गई है। अब किसी किसान की फसल खराब हो रही है या फिर फसल में किसी तरीके की बीमारी है तो वह किसान तत्काल उस फसल का फोटो वॉटसऐप पर भेज कर ओपीडी में बैठे डॉक्टर से सलाह और उसका इलाज ले सकता है। यानी घर बैठे किसान की खराब और बीमार फसल ठीक हो सकती है।

जैविक खेती करें किसान

किसान कीट-व्याधि युक्त फसल का फोटो वॉटसऐप पर भेजकर मोबाइल पर ही हल जान सकते हैं। हाल ही में हरदा में प्रदेश की प्रथम फसल ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। हरदा में 37 लाख 12 हजार रुपए की लागत से नव-निर्मित कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासकीय भवन का शुभारंभ भी किया गया। सरकार ने किसानों से आह्वान किया है कि वे भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए धीरे-धीरे रासायनिक खेती को जैविक खेती में बदलें। अब सभी जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र फसलों के उपचार के लिए फसल ओपीडी को शीघ्रता से प्रारंभ किया जाएगा।

प्रदेशभर में खुलेगी ओपीडी

कृषकों को उनकी फसल में लगने वाली कीट-व्याधि की पहचान तथा त्वरित उपचार के उपाय मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए ही प्रदेश में ओपीडी खोली जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर गांव में किसान चौपालों का आयोजन कर फसल ओपीडी की जानकारी प्रदान करें।

कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों को रबी और खरीफ की फसलों में लगने वाली बीमारियों एवं उनके उपचार के संबंध में कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फसल ओपीडी हरदा में खोली गई है। इसके बाद हर जिले में सरकार का फसल ओपीडी खोलने का पूरा प्लान है।
कमल पटेल, कृषि मंत्री

- गांव में स्व-रोजगार के लिए तैयार करेंगे नए पाठ्यक्रम
- कुरीतियों की समाप्ति के लिए महाविद्यालय आगे आएंगे

विवि और कॉलेज पिछड़े गांवों को लेंगे गोद

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक गांव को गोद लेकर वहां सचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे ग्राम में विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। ग्राम के विकास के लिए कुलपति, प्राचार्य और विद्यार्थियों की भूमिका अहम रहेगी। मप्र में शीघ्र ही यह पहल होगी। साथ ही क्षेत्र विशेष के विकास के अलावा सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए भी अब महाविद्यालय आगे आएंगे। युवा शक्ति का इसमें उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में कुछ अन्य नवाचार भी किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग कुछ ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करेगा जो ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार और विभिन्न संस्थाओं में प्लेसमेंट के लिए तैयार करेंगे। इससे सरकारी नौकरी पर निर्भरता को घटाया जा सकेगा। विशेष रूप से कृषि और पशुपालन से संबंधित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छात्रों की होगी अहम भूमिका

पिछड़े गांव में इसके पहले राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां आंशिक तौर पर ऐसी सीमित गतिविधियां करती रही हैं। अब समग्र ग्राम विकास को केंद्र में रखकर कार्य किया जाएगा। यह योजना शासन स्तर पर बनाई जाएगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाएं पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य गांवों के लोगों को मिले, इसके लिए कॉलेज का स्टाफ और छात्र अहम भूमिका निभा सकते हैं।

इनका कहना है

सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक पिछड़े गांव को गोद लेकर गांव में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे गांव में विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। ग्राम के विकास के लिए कुलपति, प्राचार्य और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। शीघ्र ही यह पहल की जाएगी। नई शिक्षा नीति में रोजगार मूलक पशुपालन, कृषि जैसे सब्जैक्ट भी शामिल करने की तैयारी भी है।
डॉ. मोहन यादच, उच्च शिक्षा, मंत्री

नई तकनीक से उत्पादन भी दस गुना तक बढ़ेगा

अब हवा में उगेगा आलू

अब किसानों को जमीन-मिट्टी की जरूरत नहीं

संवाददाता, भोपाल

कृषि के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग हो रहे हैं। फसल उगाने के लिए नई-नई विधियां सामने आई हैं। जिससे किसानों को ज्यादा आमदनी हो रही है। अब हत बात करते हैं आलू की। आलू रसोई की बहुत की महत्वपूर्ण सब्जी है जो लगभग हर सब्जी के साथ उपयोग में लाई जाती है। पर लोगों को ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि हवा में आलू उगेंगे। लेकिन अब नई तकनीक से ये संभव है। अब आलू उगाने के लिए जमीन और मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने ऐसा करके दिखा दिया है। इस तकनीक को एरोपोनिक तकनीक कहा जाता है और इससे पैदावार भी दस गुना अधिक होगी। किसान अब बिना जमीन और मिट्टी के आलू की खेती कर सकेंगे। इस तकनीक से आलू की फसल भी अधिक होगी। अब किसान परंपरागत खेती की जगह इस नई तकनीक से भी आलू उगा सकेंगे। गौरतलब है कि आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, करनाल का इंटरनेशल पोटेटो सेंटर के साथ एमओयू हुआ है। इसके बाद ही भारत सरकार ने एयरोपोनिक तकनीक से आलू की खेती करने की अनुमति दे दी है।

जमीन की जरूरत नहीं

डॉ. मुनीश सिंगल का कहना है कि एयरोपोनिक तकनीक में जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधों को दिए जाते हैं वह लटकती हुई जड़ों से दिए जाते हैं। इस तकनीक में मिट्टी और जमीन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस तकनीक की मदद से आलू का बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। डॉ. मुनीश का ये भी कहना है कि इस तकनीक की वजह से किसी भी तरह के मिट्टी जनित रोगों का खतरा भी नहीं रहता है। परंपरागत खेती के मुकाबले एयपोपोनिक तकनीक से ज्यादा संख्या में पैदावार होती है।

इनका कहना है

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने हवा में आलू उगाने का कारनामा कर दिखाया है। तीन सालों से किया जा रहा प्रयोग सफल हुआ। संस्थान एरोपोनिक नामक नई तकनीक से बिना मिट्टी के हवा में आलू उगाने की यह विधि ईजाद की है। एरोपोनिक सुविधाओं से आलू को किसानों तक कम समय में पहुंचाने में मदद मिलेगी।

■ **डॉ. चरण दास महंत**, केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री

आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए सीपीआरआई की मदद से एक सिस्टम भी लगावाया गया है जो बीज के उत्पादन की क्षमता को तीन से चार गुना तक बढ़ा रहा है। एयपोपोनिक तकनीके से सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के किसानों को भी फायदा होगा।

■ **शार्दुल शंकर**, विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल

एरोपोनिक तकनीक में जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधों को दिए जाते हैं वह लटकती हुई जड़ों से दिए जाते हैं। इस तकनीक में मिट्टी और जमीन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और आलू काफी अच्छी मात्रा मे पैदा भी होते हैं। एरोपोनिक तकनीक में आलू पैदा करने से आलू की पैदावर कई गुना ज्यादा होती है। एरोपोनिक तकनीक से पूरे भारत में हवा में आलू उगाए जा सकते हैं।

■ **डॉ. मुनीश सिंगल**, एरोपेनिक तकनीक विशेषज्ञ

कम लागत में किसान कमाएं ज्यादा मुनाफा

देश के कई हिस्सों में आलू की खेती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप स्थित गंजबासोदा के कुरावद गांव की बात ही कुछ और है। जानकर ताज्जुब होगा कि छोटे से गांव में पैदा हुए आलू का निर्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, आंध्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में होता है। गांव के ज्यादातर लोग पुखराज किस्म के आलू की खेती करते हैं और इसकी पैदावार प्रति बीघा 120 क्विंटल तक होती है। हालांकि, इस गांव में आलू की शतलज, 3797, 166 सहित कई किस्में भी बोई जाती हैं, जिनकी पैदावार भी बेहतरीन होती है। इस खेती में यहां के किसानों से सालों से लगे हैं और काफी मुनाफा भी कमाते हैं। कई किसान तो करोड़ों कमाते हैं।

आलू की खेती से सालाना लाखों की आय

ऐसी मिट्टी में पैदा होते हैं आलू

यूं तो आलू को किसी मिट्टी (क्षारिय के अलावा) में बो सकते हैं, लेकिन इसके सबसे बेहतरीन बलुई-दोमट मिट्टी है। इसके अलावा ऐसी भूमि का चयन करना होगा, जहां पर पानी निकासी की सुविधा हो। साथ ही अच्छी पैदावार के लिए रोगमुक्त बीजों की भी आवश्यकता होती है। वहीं, समय-समय पर कीटनाशक और खाद-उर्वरक का प्रयोग भी जरूरी है। इससे पौधे पर कीड़े नहीं लगते हैं और आलू के पौधे भी काफी उन्नत होते हैं।

हर राज्य में आलू की खेती

भारत में तमिलनाडु और केरल को छोड़ दें तो आलू की खेती हर राज्य में होती है, जिसका औसत उपज 152 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हालांकि, इतनी खेती होने के बावजूद यह दुनियाभर में होने वाले आलू के औसत पैदावार से काफी कम है। अगर किसान भी इस खेती में किस्मत आजमाते हैं तो हर साल लाखों कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको मूलभूत बातों के बारे में जानना जरूरी है।

उर्वरक का प्रयोग और सिंचाई

आलू की खेती में खाद्य-उर्वरक का प्रयोग अनिवार्य है। इस वजह से फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर्याप्त मात्रा में डालें। इससे पौधे की पत्तियां तो बढ़ती ही हैं। साथ ही साथ उनके कंदमूल का आकार भी तेजी से बढ़ता है। वहीं, सिंचाई की बात करें तो पौधे जब उग जाएं तब पहली बार पटवन करना चाहिए। वहीं इसके 15 दिन बाद दोबारा पौधों में पानी देना चाहिए।

बोवनी का सही तरीका

आलू की फसल बोते समय उनके बीच की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इससे पौधों को रोशनी, पानी और पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं। आलू की क्यारियों के बीच की दूरी कम से कम 50 सेंटीमीटर तो दो पौधों के बीच की दूरी 20-25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इससे कम दूरी रखते हैं तो आलू के साइज छोटे होंगे और ज्यादा दूरी रखते हैं तो साइज बड़े, लेकिन उपज कम हो जाएगी।

सीईओ, सरपंच और सचिवों को जिम्मा

गांवों में पंचायत विभाग उगाएगा चारा

आवारा मवेशियों को मिलेगा भोजन

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में अब पंचायत विभाग आवारा मवेशियों के लिए भरपेट खाने की व्यवस्था के तहत चारा उगाने का भी काम करेगा। यह चारा प्रदेश में बेसहारा घूमने वाले पशुओं के लिए उगाया जाएगा। यह काम प्रदेश में ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले गांवों में किया जाएगा। इसका जिम्मा सरपंच-सचिव और जनपद-जिला पंचायत अधिकारियों को सौंपा गया है। प्रदेश में पहली बार इस तरह का अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत और गांवों में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर चारा उगाने पर खर्च होने वाली राशि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से की जाएगी। हाल ही में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के आयुक्त द्वारा कलेक्टरों, जिला पंचायत सीईओ और मनरेगा के अफसरों को लिखे गए पत्र में कहा है कि ग्रामीण इलाकों के मनरेगा के तहत पात्र लोगों को प्रोत्साहित कर उनकी खेती को ज्यादा लाभदायक बनाना है।

हर पंचायत में गौचर भूमि

चारे की कमी की वजह से बीते सालों में पशुओं की संख्या में लगातार कमी आई है। यही वजह है कि अब पशुओं के लिए हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता तय करने के लिए हर जिले चारे की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध 2 प्रतिशत गौचर भूमि में मुख्यमंत्री गौचर भूमि विकास उपयोजना के तहत काम किए जाएं।

कार्ययोजना बनाई जाए

राज्य सरकार ने कहा है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध गोवंश के हिसाब से चारे की मात्रा का आंकलन किया जाए। उपलब्ध चारे की मात्रा छोड़कर शेष हरे चारे के उत्पादन के लिए विकास के कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए।

सिंचाई सुविधा जरुरी

स्थल के चयन में यह देखा जाना जरुरी रहेगा कि उक्त जमीन का उपयोग केवल चारागाह के लिए ही किया जाए। इसके अलावा चयनित जमीन पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था का हो। इसमें चारागाह स्थल पर या समीप में पानी का स्त्रोत के रूप में सामुदायिक कूप, तालाब, नदी नाला होने पर चेक डेम निर्माण कार्य पृथक से स्वीकृत कर विकसित भी किया जाएगा। अगर चारागाह स्थल पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो इसकी व्यवस्था मनरेगा से की जाएगी।

एक हजार किसानों को प्रोत्साहित करेगी सरकार

बुंदेलखंड में पान किसानों के आएंगे अच्छे दिन

संवाददाता, भोपाल

पिछले तीन दशक से पान की खेती सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन के दौर में उसके अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। लेकिन अब किसानों की चिंता और खत्म होने की कगार पर पहुंची मप्र की पान की विरासत को शिवराज सरकार सहेजने की कवायद में जुट गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि बुंदेलखंड के एक हजार से ज्यादा पान की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बुरे दौर से गुजर रहे किसानों के अच्छे दिन आएंगे। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के सभी पान बरेजे अब हाई-टेक होंगे और उन्हें शीघ्र ही ग्रीन हाउस में तब्दील कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड के छतरपुर में प्रायोगिक तौर पर किए गए इस कार्य के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। वर्तमान में पान बरेजे घास-फूस के होते हैं, जिसके कारण विपरीत मौसम में ही पानों को बहुत नुकसान हो जाता है। इन बरेजों में अब बांस-बल्ली और घास-फूस की जगह शेड नेट दिए जा रहे हैं और बांस की जगह लोहे के एंगलों का उपयोग किया जा रहा है। इससे बरेजों में स्थायित्व तो आया ही है, पान की क्वालिटी भी सुधरी है।

खेती कम होने के प्रमुख कारण

- तापमान बढ़ रहा, जल स्तर गिर रहा
- कोल्डस्टोरेज की व्यवस्था नहीं
- यातायात की पर्याप्त सुविधा नहीं
- बारिश कम होने से सूख रहे तालाब
- सिंचाई को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा

ऐसे मिल सकता बढ़ावा

- पान कृषि के लिए पर्यावरण के अनुकूल ही बरेजा निर्माण की अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- पान की नवीनतम प्रजातियों की पहचान की जानी चाहिए, जो अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण के अनुकूल हों।
- जैविक उत्पादों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जैविक खाद के उपयोग से उत्पन्न पान के पत्ते 15 दिनों तक ताजे रह सकते हैं।
- पान को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्डस्टोरेज व परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पान व्यापार से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सहकारी समितियों के जरिए कार्य किया जाना चाहिए।

दस फीसदी रह गई पान की खेती

बुंदेलखंड विवि से 2017 में पान की खेती पर छात्रा द्वारा किए गए एक शोध में यह तथ्य सामने आए कि बुंदेलखंड में पान खेती सिमटती जा रही है। किसान पलायन कर खेती के बजाए मजदूरी करने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन और संसाधन की कमी के चलते बुंदेलखंड में पान की खेती दस फीसदी रह गई है। यही हालात रहे तो कुछ सालों बाद पान की खेती यहां समाप्त हो सकती है। नुकसान को देखते हुए अब यह हालात पैदा हो गए हैं कि लोग पान की खेती के लिए अपनी जमीन नहीं दे रहे हैं।

मौसम की बेरुखी डुबाया

जलवायु परिवर्तन और मौसम के उतार-चढ़ाव ने इस जोखिम भरी खेती को बेहद संवेदनशील बना दिया है। पिछले कुछ साल के दौरान मानसून में बारिश काफी कम हुई है। लगातार सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के जलस्रोतों में पानी की बेहद कमी है। पानी की अनुपलब्धता का सबसे बुरा असर पान की खेती पर पड़ा है, क्योंकि इसे गर्मियों में प्रतिदिन 4-5 बार पानी देना पड़ता है।

मीठा पत्ता पान पर फोकस

मध्यप्रदेश का बंगला पान पूरे प्रदेश के कोने-कोने में तो लोकप्रिय है ही, इसे उत्तरप्रदेश के महोबा तक यह अपने लाजवाब स्वाद के कारण पान के शौकीनों के मुख की शान बना हुआ है। अब प्रदेश के किसान मीठा पत्ता पान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पान में पाला भी बेअसर

पान की कटिंग और ग्रोथ बढ़ी है। इसका प्रभाव हाल ही में पड़े पाले के समय देखने को मिला। जिन बरेजों को हाई-टेक किया गया है, वहां पान को कम नुकसान हुआ है जबकि परंपरागत बरेजों का पान पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसके अलावा, पान की खेती करने वालों ने ड्रिप सिंचाई को भी अपनाया है। इससे कम पानी में पर्याप्त और प्रभावी सिंचाई होती है।

मप्र सरकार दे रही अनुदान

मप्र सरकार द्वारा पान उत्पादकों को रुपए 30 हजार रुपए से ज्यादा प्रति बरेजा (500 वर्ग मीटर) अथवा 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को अपने बरेजे हाई-टेक करने को प्रोत्साहित करने के लिए यह शर्त रखी गयी कि, जो उत्पादक इन साधनों को अपनाएंगे, उन्हें ही अनुदान की पात्रता होगी।

चमत्कारी परिणाम

शुरू में तो किसानों ने इसका विरोध किया, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह पर शर्त मान ली। इसके चमत्कारी परिणाम सामने आए। पान के पत्ते का आकार बड़ा और वे ज्यादा स्वस्थ रूप से विकसित हुए। अब किसान खुद इसमें रुचि ले रहे हैं। इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम छतरपुर, सागर और नरसिंहपुर में हुआ है।

19 जिलों में पान की खेती

मध्यप्रदेश के 19 जिलों में बंगला पान की खेती की जाती है। ये जिले हैं- जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, रायसेन, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, ग्वालियर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, खंडवा, होशंगाबाद, रीवा, सागर, सतना और इंदौर।

मध्यप्रदेश में वानिकी विकास के नए आयाम गढ़ता वन विभाग

विजय शाह, वन मंत्री, मप्र

प्रदेश में स्थापित वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रभावी पहल की गई है। इसी का परिणाम है कि वनों के साथ-साथ इस पर आश्रित ग्रामीणों की स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है। वानिकी विकास की दिशा में अनेकानेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप वन और वन्य-प्राणियों के बेहत्तर प्रबंधन के साथ ही वनों पर आश्रित वनवासियों के जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सका है। यह सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। देश में सबसे अधिक बाघ इसी प्रदेश में है। पिछले साल बाघों की संख्या 526 होने के साथ प्रदेश को एक बार दोबारा टाईगर स्टेट का दर्जा मिला है। इसी तरह तेंदुओं की संख्या के मामले में भी हमारे प्रदेश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य को पीछे छोड़कर तेंदुआ स्टेट दर्जा मिलने का गौरव हासिल किया है। प्रदेश में 3 हजार 421 तेंदुओं की संख्या पाई गई। देश में उपलब्ध तेंदुओं की संख्या में से 25 प्रतिशत अकेले मध्यप्रदेश में पाए गए हैं। प्रदेश में 13 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभ्यारण्य स्थित है। मुकुन्दपुर में सफेद बाघ सफारी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान-जू भोपाल और रायसेन में तितली पार्क है। वन्य-प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्यप्रदेश में 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर (64,68,900 हेक्टेयर) कुल वन क्षेत्र है, जो राज्य के भू-भाग का 30.72 फीसदी और देश के कुल वन क्षेत्र का तकरीबन 12.38 फीसदी है। प्रदेश की वन नीति-2005 से लागू है। वन विभाग दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए उनके संवर्धन के साथ वनों पर आश्रित ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में असरदार पहल की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हरेक साल तकरीबन 7 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बांस, चारा उत्पादन एवं लाख उत्पादन के माध्यम से एक लाख से अधिक ग्रामीणों को वानिकी गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग में प्रत्येक वन मंडल द्वारा 10 वर्ष की कार्य-योजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। योजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण भी किया जाता है। इसके साथ ही बिगड़े वनों का सुधार एवं सघन वनों में पुनरउत्पादन के लिए सहायक वन वर्धनिक कार्य, सीमा एवं कठिन सुरक्षा के कार्य कराए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप-2023 के रूप में महत्वाकांक्षी पहल को मूर्त रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कार्य-योजना तैयार की जा रही है। इसमें बफर में सफर मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा, टाईगर सफारी विकसित करना, लकड़ी/बांस के प्र-संस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास, 20 बांस कलस्टरों का व्यवस्थित विकास, प्रदेश की वनोपज का मध्यप्रदेश उत्पाद के रूप में जीआई रेगिंग, वनोपज के बेहतर मूल्य के लिए वनोपज मूल्य संवर्धन विकास, वन आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन, उपयुक्त हैबिटेट में चीता को लाना, बाघों का घनत्व बढ़ाने और वन स्थिरता को बढ़ावा दिए जाने के लिए बाघों को अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में शिफ्ट करना, वनों के बाहर बृक्ष आवरण बढ़ाने में शासकीय गैर वन भूमि पर पौधरोपण की पहल और भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर पारदर्शिता को बढ़ाने जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में 11 अनुसंधान और विस्तार वृत्तों की 170 अनुसंधान और विस्तार रोपणियों में विभिन्न प्रजाति के 4 करोड़ 13 लाख पौधे उपलब्ध हैं। विभागीय पौधरोपण एवं गैर-वानिकी क्षेत्रों में रोपण के लिए आवश्यक पौधो की तैयारी, उपलब्ध पौधों का रख-रखाव और अनुसंधान विस्तार नर्सरियों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। रोपणियों के पौधों के ऑनलाईन संधारण के लिए नर्सरी मैनेजमेन्ट विकसित किया गया है। कुछ रोपणियों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर रोपणियों की सुरक्षा और निगरानी की जा रही है। विभाग की कार्यप्रणाली में जन का महत्वपूर्ण स्थान है। वन-जन को समन्वित कर वानिकी में भागीदारी का अंश बढ़ाने के साथ ही जन की सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन की विचारधारा को अपनाया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन में 10 हजार 141 ग्राम वन समिति, 4419 वन सुरक्षा समिति और 1044 ईको विकास समिति गठित हैं। वन समितियों की कुल संख्या 15 हजार 604 है। इनके माध्यम से 79 हजार 705 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है। वन समितियों में 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता आरक्षण के साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में से एक महिला की नियुक्ति अनिवार्य की जाकर महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाया गया है।

मौसम की अनिश्चितता, खेती पर गहराता संकट और आत्महत्या करते किसान

शिरीष खरे

महाराष्ट्र में अमरावती जिले के दापोरी खुर्द में बीती 15 जनवरी को एक खेतीहर मजदूर दिनेश उइके (40 वर्ष) ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। उनके परिजन बताते हैं कि दिनेश उइके ने बढ़ती मंहगाई और कोई काम न होने से घबराकर ऐसा किया। हालांकि, गंभीर स्थिति में वे उन्हें अमरावती जिला अस्पताल लाए थे, लेकिन, उपचार के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिवार में बूढ़े माता-पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं।

महाराष्ट्र में अमरावती जिले के दापोरी खुर्द में बीती 15 जनवरी को एक खेतीहर मजदूर दिनेश उइके (40 वर्ष) ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। उनके परिजन बताते हैं कि दिनेश उइके ने बढ़ती मंहगाई और कोई काम न होने से घबराकर ऐसा किया। हालांकि, गंभीर स्थिति में वे उन्हें अमरावती जिला अस्पताल लाए थे, लेकिन, उपचार के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिवार में बूढ़े माता-पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं। महाराष्ट्र में हर साल औसतन तीन हजार किसान आत्महत्या करते हैं। वर्ष 2020 में दो हजार 270 किसानों ने आत्महत्याएं कीं। हालांकि, यह वर्ष 2019 के मुकाबले 262 कम है। इस साल राज्य के कोकण में अंचल में आत्महत्या नहीं हुई है। यह आंकड़े राज्य के राहत व पुनर्वास विभाग ने सूचना के अधिकार द्वारा मांगी गई जानकारी में दिए हैं। हालांकि, इन आंकड़ों को जारी करते हुए विभाग ने दावा किया है कि वर्ष 2020 में नागपुर और नासिक संभाग को छोड़ दें तो सभी संभागों में किसान आत्महत्या के प्रकरण कम हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में हुईं किसानों की आत्महत्या से जुड़े ये आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं विदर्भ के अमरावती संभाग में हुईं। इस दौरान अमरावती संभाग में सबसे अधिक एक हजार 893 किसानों के आत्महत्या से जुड़े प्रकरण सामने आए हैं। अमरावती संभाग के यवतमाल जिले में सबसे अधिक 295 किसान आत्महत्याओं के प्रकरण उजागर हुए।

दूसरे स्थान पर मराठवाडा का औरंगाबाद संभाग है, जहां इन दो वर्षों में एक हजार 528 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसके बाद तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश: नाशिक और नागपुर संभाग हैं, जहां वर्ष 2019 के मुकाबले किसान आत्महत्याओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन दो वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या नाशिक और नागपुर संभाग में क्रमश: 774 और 456 है। एक ओर, राज्य सरकार का राहत व पुनर्वास विभाग वर्ष 2020 में किसान आत्महत्याओं में आई इस कमी के पीछे कुछ कारण गिना रहा है। इसका कहना है कि राज्य की महागठबंधन वाली नई सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर दिया, जिससे पिछले साल किसानों को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिली है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की ओर से भूमि राजस्व और बिजली के बिलों में भी छूट दी गई है। विभाग का यह भी दावा है कि विद्यार्थियों की परीक्षा-शुल्क में दी गई माफी भी किसान परिवारों के लिए कुछ हद तक मददगार साबित हुई है। दूसरी तरफ, यह तथ्य भी स्पष्ट हो रहा है कि आत्महत्या करने वाले किसानों में एक बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें राज्य सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिला। पिछले वर्ष आत्महत्या करने वाले किसानों में सिर्फ 920 किसानों को ही राज्य सरकार से एक लाख रुपए का अनुदान मिला था। पिछले वर्ष भी विदर्भ में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन, इनमें से अधिकतर को राज्य सरकार की ओर से अनुदान राशि हासिल नहीं हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 में विदर्भ के 990 आत्महत्या करने वाले किसानों में 411 को राज्य सरकार ने अनुदान के लिए पात्र नहीं माना था। विदर्भ राज्य में किसानों की आत्महत्या के लिए पहचाना जाता है। आत्महत्या करने के बाद सरकार की तरफ से किसान परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाती है, लेकिन, आत्महत्या करने से पहले ही इन आत्महत्याओं के मूल में छिपे कारण को सुलझाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। राज्य के इस अंचल में पिछले साल एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में किसानों के मानसिक अवसाद को समझने की कोशिश की गई थी। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि विदर्भ के साठ प्रतिशत किसानों को मानसिक उपचार की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण को करने वाली संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का मानना था कि विदर्भ के किसानों को मानसिक परामर्श देने के लिए सरकार आगे आए और उनके लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करे इस सर्वेक्षण में विदर्भ के 34.7 प्रतिशत किसानों में गंभीर मानसिक बीमारियों से जुड़े लक्षण पाए गए थे। इनमें 55 प्रतिशत किसानों की स्थिति चिंताजनक थी।

किसानों के नजरिए से चिंता की बात है कि यह लगातार दूसरा साल है जब खराब मौसम और अनियमित बरसात के कारण यहां कपास की फसल बर्बाद हुई है। दरअसल, कपास की पैदावार के मामले में महाराष्ट्र का विदर्भ अंचल अग्रणी रहा है, लेकिन, यहां प्रदीप साल्वे की तरह यह सफेद सोना उगाने वाले ज्यादातर किसानों को बेमौसम बरसात के कारण काफी नुकसान उठाना प? रहा है. इस साल हालत यह है कि यहां खरीफ मौसम की इस फसल को उगाने वाले किसान 60 प्रतिशत तक घाटा सह रहे हैं। यही वजह है कि यहां के किसानों का बजट गड़बड़ा गया है। जाहिर है कि इस आर्थिक नुकसान का असर उनके आगामी सीजन पर भी पड़ेगा। विदर्भ में खास तौर से यवतमाल जिले को कपास उत्पादन के कारण जाना जाता है। लेकिन, पिछले कई वर्षों से विदर्भ के अन्य जिलों की तरह यवतमाल जिला भी किसान आत्महत्याओं के कारण चर्चा में रहा है। ऐसा इसलिए कि यहां पिछले कुछ दशकों से कृषि क्षेत्र में आए संकट के भंवरजाल में फंसे किसान इससे बाहर नहीं निकल पा रहे है। इसके बावजूद यहां के किसान मौजूदा परिस्थितियों को बदलने के लिए हर साल लगातार अपने खेतों में बोवनी कर रहे है।

प्रश्न है कि विदर्भ का एक कपास उत्पादक किसान बंपर फसल की उम्मीद पर प्रति एकड़ अपने खेत में सालाना किन-किन चीजों पर करीब कितनी लागत खर्च करता है। इस बारे में अमरावती जिले के एक कपास उत्पादक किसान नीलेश तायडे बताते हैं कि एक अच्छी फसल लेने के लिए उनकी मेहनत खेतों को समतल बनाने से शुरू होती है। इसके बाद वे खेत से कचरा निकालने के बाद बीज, खाद और कीटनाशक खरीदते हैं, फिर कुछ मजदूरों को मजदूरी देकर बुवाई करते हैं। कपास के लिए एक निश्चित अवधि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तब जाकर जब फसल तैयार होती है तो उन्हें कपास की छटाई करनी पड़ती है। इतना करने के बाद जब वह अपना कपास खेत से ढोकर बाजार में लाता है तो माल बेचने के साथ उसे फिर कड़ी कसरत करनी पड़ती है।

समृद्ध भविष्य की राह पर प्रदेश की कृषि व्यवस्था

डॉ. आनन्द शुक्ल

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वहां की कृषि उपज के आधार पर सुनिश्चित होती है। ऐसे में मप्र को लेकर एक बात स्पष्ट हो गई है कि यहां रबी और खरीफ की पैदावार में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। इसके पीछे राज्य सरकार की सुनियोजित लक्ष्य और प्रदेश के किसानों को लगातार दी जाने वाली सहायता है। इसकी बुनियाद एक दशक पहले भाजपा शासन काल में ही रख दी गई थी। जिसका परिणाम था कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो चुका है। 2024 तक इसे 80 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी सुनिश्चित है। इसके लिए राजनैतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की मजबूती ही सबसे बड़ा आधार है। सुचारू रूप से खेतों को पानी मिले और सिंचाई होती रहे इसके लिए जल का भंडारण, नहरों की व्यवस्था तथा निरंतर बिजली की उपलब्धता राज्य सरकार ने सुनिश्चित की है। मप्र बीते 10 सालों में भारत सरकार के कृषि कर्मण अवार्ड को लगातार 5 बार हासिल करने में सफल रहा। पिछले 3 वर्षों से कृषि के मामले में देश में सबसे इंप्रूव्ड राज्य के रूप में अपनी पहचान बना लिया है। बीते वर्ष 2020 में एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन रबी (गेहूं) का उपार्जन करके पूरे देश में नम्बर 1 का दर्जा हासिल किया है।

राज्य की चौथी बार कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कृषि क्षेत्र की ओर और विशेष ध्यान दिया है। इसी का परिणाम है कि कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मप्र देश में सबसे आगे है। अधोसंचरना विकास के लिए आत्मनिर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। पिछले 9 माह में दो करोड़ 10 लाख किसान हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 46 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सहायता के रूप में जारी की जा चुकी है। उद्यानिकी फसल बीमा के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। किसानों का हित संवर्धन किसी भी प्रकार से न बाधित हो इसके लिए बैंकों की स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार ने बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पिछले 9 माह में शिवराज सरकार ने 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सात सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। कृषि की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आगामी 3 वर्षों की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। जिसके तहत फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, कृषि में जोखिम प्रबंधन हेतु नवीन तथा उन्नत तकनीक के कृषि क्षेत्र में शीघ्र उपयोग को प्रोत्साहित करना, कृषि अधोसंरचना का विकास, प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, एक राष्ट्र एक बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विपणन कानूनों में सुधार, कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादनों का मूल्य संवर्धन, राज्य में पशुपालन विकास पर बल के साथ-साथ रोजगार में वृद्धि के लिए मत्स्यपालन एवं एवं रेशम पालन के विकास जैसे लक्ष्यों को शामिल किया गया है।

प्रदेश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उससे यह तस्वीर निकलकर अब सामने आने लगी है कि आने वाले निकट भविष्य में मप्र देश के अन्य राज्यों का विकास के मामले में, आत्मनिर्भरता के मामले में रोलमॉडल बनेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि समृद्धि की राह पर मप्र की कृषि व्यवस्था अब आगे बढ़ चली है।

श्योपुरः सब्जी-फल की खेती से सालाना कमा रहे लाखों

केवट समाज की नैयया पार लगा रही जैविक खेती

संवाददाता, श्योपुर

नदियों में नाव चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले केवट समाज के लोग पुल बन जाने के बाद से श्योपुर जिले की नदियों के किनारे फल-सब्जी की जैविक खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। साल 1994 तक चंबल नदी पर पुल नहीं होने की वजह से जिले के केवट समुदाय के कई परिवार नाव चलाकर मप्र के यात्रियों को नदी पार राजस्थान सीमा में पहुंचाकर आजीविका चलाते थे, लेकिन जैसे ही नदी पर पुल बनाया गया, वैसे ही यात्रियों ने नाव में बैठना बंद कर दिया।

इससे केवट समुदाय के लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नदियों द्वारा छोड़े जाने वाले मिट्टी के मलबे में सब्जी और फल की खेती करने का काम शुरू किया। इससे अब वह लाखों सालाना कमा रहे हैं। केवट समुदाय के ग्रामीण लंबे समय से चंबल और पार्वती नदियों के किनारों पर बसे गांवों में ही निवास करते आ रहे हैं।

पुल बनते ही छिना रोजगार

पहले यहां केवट समाज की आय का मुख्य स्रोत नदियों में नाव चलाकर यात्रियों को इस पार से उस पार उतारकर मिलने वाली मजदूरी थी, लेकिन जैसे ही मप्र को राजस्थान से जोड़ने वाली चंबल नदी पर पाली के पास पुल का निर्माण कर दिया गया और दूसरे घाटों पर नाव की बजाय स्ट्रीमर चलना शुरू हुए वैसे ही इस समुदाय के लोगों का रोजगार छिन गया। इसके बाद से इस समाज के लोगों ने नदियों के किनारे पर जैविक खेती करने का काम शुरू कर दिया। इससे वह लाखों कमा रहे हैं।

बरसात में मलबा छोड़ती हैं नदियां

बरसात के सीजन में चंबल और पार्वती सहित अन्य नदियां उफान पर पहुंच जाती हैं। इस सीजन में नदियों के किनारे फसलें उगा पाना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर के महीने में नदियों का जलस्तर कम होता जाता है। वैसे-वैसे किनारों पर मिट्टी का मलबा भी जमा होता जाता है। यह मलबा बेहद उपजाऊ होता है और जैविक खाद का काम करता है। इसलिए इसे सूखने के बाद केवट समाज नदियों के किनारों पर हकाई-जुताई करके फल और सब्जी की खेती करते हैं।

15 हजार खर्च, 50 हजार आय

नदियों के किनारों पर केवट समाज के लोग सर्दी के सीजन में कद्दू, पेठा, लौकी सहित अन्य सब्जियों की पैदावार करते हैं। वहीं गर्मियों के सीजन में खरबूजा, बटई, ककड़ी, तरबूज आदि फलों की खेती करते हैं। उन्हें वह दिल्ली, जयपुर, कोटा में सप्लाई करवाते हैं। इससे उन्हें अच्छी आय होती है। किसानों की मानें तो प्रति बीघा पर 15 हजार का खर्चा होता है और आय 50-60 हजार की प्राप्त होती है, जो दूसरी फसलों से कई गुना अधिक है।

इनका कहना है

1994 में चंबल नदी पर पाली पुल बनाए जाने के बाद हमारा नाव का धंधा पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और नदी द्वारा छोड़े गए मलवे में फल और सब्जी की खेती करना शुरू किया। इससे हमारी आय पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हमारे समाज के ज्यादातर लोग अब इसी काम को कर रहे हैं।

तुलसीराम केवट, ग्रामीण सामरसा

हमारे गांव में केवट परिवार के लोग पहले नाव चलाते थे लेकिन, अब यह कद्दू, पेठा और तरबूज आदि फल-सब्जी की खेती करके अच्छा धन कमा रहे हैं। फल और सब्जी भी बिना केमिकल के होते हैं। इसकी श्योपुर ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े शहरों में खूब डिमांड रहती है।

रामसिंह मीणा, सरपंच दांतरता कलां

सूखे और गोल नारियल का बढ़ाया एमसएपी

» आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात

» 2021 सीजन के लिए 10335 रुपए प्रति क्विंटल किया

» गोल कोपरे के एमएसपी में भी 300 रुपए का इजाफा

एजेंसी, नई दिल्ली

नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सूखे नारियल और गोल नारियल का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट में सूखे नारियल का एमएसपी 375 रुपए प्रति क्विंटल और गोल नारियल का एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में 2021 सीजन के लिए नारियल की एमएसपी पर मुहर लगी। फेयर एवरेज क्वालिटी वाले सूखे नारियल की एमएसपी बढ़ाकर 10335 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, इसका लागत मूल्य 6805 है। 2020 सीजन के लिए इसकी एमएसपी 9960 रुपए प्रति क्विंटल थी। जबकि बॉल नारियल के लिए एमएसपी को बढ़ाकर 10,600 रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले साल 10,300 रुपए प्रति क्विंटल थी।

किसानों की बल्ले-बल्ले

सूखे नारियल की एमएसपी उसके उत्पादन लागत से 52 परसेंट ज्यादा है, जबकि बॉल नारियल की एमएसपी उसके उत्पादन लागत से 55 परसेंट ज्यादा है। 2021 सीजन के लिए नारियल की एमएसपी उसी सिद्धांत पर है, जिसमें तय किया गया था कि एमएसपी का स्तर औसत उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना होना चाहिए।

इनका कहना है

बाजार कीमतें आमतौर पर एमएसपी से ज्यादा होती हैं। कभी भी कीमतें सपोर्ट प्राइस से नीचे आती हैं तो सरकारी एजेंसियां किसानों के हितों की रक्षा के लिए उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगी। दोनों ही केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं, जो नारियल उगाने वाले राज्यों में प्राइस सपोर्ट को देखती हैं। भारत गरी उगाने वाला दुनिया का नंबर एक देश है। इसका उत्पादन 12 तटीय राज्यों में खासतौर पर किया जाता है।

प्रकाश जावडेकर, सूचना और प्रसारण मंत्री

प्रदेश में 71 हजार आवारा गायों को मिला आश्रय

» सड़क पर बैठने वाले गायों के झुंड में आई कमी

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना में स्वीकृत 1004 गौ-शाला में से 963 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 905 गौ-शाला का संचालन प्रारंभ कर 71 हजार 27 निराश्रित गायों को आश्रय दिया गया है। गौ-शालाओं में निराश्रित बीमार और वृद्ध गायों को समय से चारा-पानी और उपचार मिलने से इनकी हालत बेहतर हुई है। दूसरी ओर गौ-शाला में रहने से सड़क पर बैठने वाले गायों के झुंड में भी कमी आई है। इससे गायों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगा है।

नई 2409 गौ-शाला निर्माण की मंजूरी

वर्ष 2020-21 में भी प्रदेश में 2409 गौ-शालाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 1808 गौ-शालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और 11 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। स्वीकृत गौ-शालाओं में से 44 गौ-शालाओं का विस्तार किया जा रहा है। नई स्वीकृत गौ-शालाओं में 961 का नींव स्तर, 529 का दीवाल स्तर और 356 का छत स्तर तक का काम पूरा हो गया है।

इनका कहना है

गौ-शाला संचालकों को स्वावलंबन प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जा रहा है। गोबर-गौ-मूत्र से कृषि उपयोगी उत्पाद, दैनिक उपयोग की सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। शासकीय विभागों द्वारा फिनाइल के स्थान पर गौ-फिनाइल के उपयोग के आदेश दिए गए हैं। गौ-उत्पाद सांची के आउटलेट पर भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।

प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन मंत्री

-दस समूह योजनाः नौ लाख एफएचटीसी का लक्ष्य

मध्यप्रदेश के साढ़े चार हजार गांवों में पहुंचेगा नल से जल

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में गांवों के प्रत्येक परिवार को नल के जरिये जल देने की दिशा में निरंतर एकल एवं समूह जलप्रदाय योजनाओं का कार्य हो रहा है। मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आइ जिलों के लिए मंजूर की गई 10 जलप्रदाय योजनाओं पर जल निगम द्वारा कार्यवाई प्रारंभ कर औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं। अब अगले चरण में (धरातल) पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के आठ जिलों के 4404 ग्रामों के लिए क्रियान्वित इन 10 समूह जलप्रदाय योजनाओं में 9 लाख 34 हजार 399 नल कनेक्शन लगाए जाएंगे। जलप्रदाय योजनाओं के दायरे में आने वाले सभी 4404 ग्राम शत-प्रतिशत नल कनेक्शन युक्त हो सकेंगे।

शिवपुरी की 842 गांव

प्रदेश के धार जिले की राजोंद जलप्रदाय योजना में 74, सागर जिले की मड़िया जलप्रदाय योजना में 276, आगर-मालवा जलप्रदाय योजना में 480, शिवपुरी जिले की मड़ीखेड़ा जलप्रदाय योजना में 842, गुना जिले की गोपीकृष्ण सागर जलप्रदाय योजना में 354 गांवों को नल-जल युक्त किया जाएगा।

नहीं होगी पानी की किल्लत

गुना और अशोकनगर जिले की राजघाट जलप्रदाय योजना में 1573, देवास जिले की नेमावर (हाटपिपल्या) जलप्रदाय योजना में 115 तथा सिंगरौली जिले की गोंड देवसर, बैढ़न एक तथा बैढ़न दो जलप्रदाय परियोजना में 690 ग्रामों को शत-प्रतिशत नल-जल युक्त किया जाना शामिल है।

सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी गायों की 10 नस्लें

गिर, साहीवाल और नागोरी नस्ल की गाय दूध देने में नंबर वन

भोपाल। दूध और मांस के लिए पशुओं का पालन दुनिया भर में किया जाता रहा है। इसी के साथ भारत में प्राचीन काल से ही पशुपालन व्यवसाय के रूप में प्रचलित रहा है। वर्तमान में भी यह जारी है। भारत में करीब 70 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। गांव में रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती और पशुपालन ही है। सरकार की ओर से भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं पशुओं की चिकित्सा के लिए गांव में पशु चिकित्सालय भी खोले गए हैं। इस सब के बाद भी आज पशुपालन करने वाले किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या देसी गाय के पालन को लेकर है।

देसी गाय की पहचान: भारतीय देसी गाय की नस्लों की पहचान सरल है, इनमें कूबड़ पाया जाता है, जिसके कारण ही इन्हें कूबड़ धारी भारतीय नस्लें भी कहा जाता है, अथवा इन्हें देसी नस्ल के नाम से ही पुकारा जाता है। आइए जानते हैं क्षेत्रानुसार गाय की अच्छी 10 उन्नत प्रजातियों के बारें में।

गिर नस्ल: गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान गुजरात है। गिर गाय को भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय माना जाता है। यह गाय एक दिन में 50 से 80 लीटर तक दूध देती है। इस गाय के थन इतने बड़े होते हैं। इस गाय का मूल स्थान काठियावाड़ (गुजरात) के दक्षिण में गिर जंगल है, जिसकी वजह से इनका नाम गिर गाय पड़ गया। भारत के अलावा इस गाय की विदेशों में भी काफी मांग है। इजराइल और ब्राजील में भी मुख्य रुप से इन्हीं गायों का पाला जाता है।

साहीवाल: साहीवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। इसका मूल स्थान पंजाब और राजस्थान है। यह गाय मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह गाय सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध देती हैं जिसकी वजह से ये दुग्ध व्यवसायी इन्हें काफी पसंद करते हैं। यह गाय एक बार मां बनने पर करीब 10 महीने तक दूध देती है। अच्छी देखभाल करने पर ये कहीं भी रह सकती हैं।

राठी: इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान है। भारतीय राठी गाय की नस्ल ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। राठी नस्ल का राठी नाम राठस जनजाति के नाम पर पड़ा। यह गाय राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर इलाकों में पाई जाती हैं। यह गाय प्रतिदिन 6 –8 लीटर दूध देती है।

हल्लीकर: हल्लीका गाय का मूल स्थान कनाज़्टक है। हल्लीकर के गोवंश मैसूर (कर्नाटक) में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस नस्ल की गायों की दूध देने की क्षमता काफी अच्छी होती है।

हरियाणवी: इस नस्ल की गाय का मूल पालन स्थान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। इस नस्ल की गाय सफेद रंग की होती है। इनसे दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। इस नस्ल के बैल खेती में अच्छा कार्य करते हैं इसलिए हरियाणवी नस्ल की गायें सवाज़्गी कहलाती हैं।

कांकरेज : इस नस्ल की गाय का मूल स्थान गुजरात और राजस्थान है। कांकरेज गाय राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें बाड़मेर, सिरोही तथा जालौर जिले मुख्य हैं। इस नस्ल की गाय प्रतिदिन 5 से 10 लीटर तक दूध देती है। कांकरेज प्रजाति के गोवंश का मुंह छोटा और चौड़ा होता है। इस नस्ल के बैल भी अच्छे भार वाहक होते हैं। अतः इसी कारण इस नस्ल के गौवंश को द्वि-परियोजनीय नस्ल कहा जाता है।

लाल सिंधी : इस नस्ल की गाय पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल रंग की इस गाय को अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। लाल रंग होने के कारण इनका नाम लाल सिंधी गाय पड़ गया। यह गाय पहले सिफ्र सिंध इलाके में पाई जाती थीं। लेकिन अब यह गाय पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में भी पाई जाती हैं। इनकी संख्या भारत में काफी कम है। साहिवाल गायों की तरह लाल सिंधी गाय भी सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध देती हैं।

कृष्णा वैली : इस नस्ल की गाय का मूल स्थान कर्नाटक है। कृष्णा वैली उत्तरी कर्नाटक की देसी नस्ल है। यह सफेद रंग की होती है। इस नस्ल के सींग छोटे, शरीर छोटा, टांगे छोटी और मोटी होती है। यह एक ब्यांत में औसतन 900 किलो दूध देती है।

नागोरी : इस नस्ल की गाय राजस्थान के नागौर जिले में पाई जाती है। इस नस्ल के बैल भारवाहक क्षमता के विशेष गुण के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। निमरी (मध्य प्रदेश) निमरी का मूल स्थान मध्य प्रदेश है। इसका रंग हल्का लाल, सफेद, लाल, हल्का जामुनी होता है। इसकी चमड़ी हल्की और ढीली, माथा उभरा हुआ, शरीर भारा, सींग तीखे, कान चौड़े और सिर लंबा होता है। यह नस्ल औसतन 600-954 किलो दूध देती है और दूध की वसा 4.9 प्रतिशत होती है।

खिल्लारी : इस नस्ल का मूल स्थान महाराष्ट्र और कर्नाटक के जिले है और यह पश्चिमी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। इस प्रजाति के गोवंश का रंग खाकी, सिर बड़ा, सींग लम्बी और पूंछ छोटी होती है। गलबल काफी बड़ा होता है। खिल्लारी प्रजाति के बैल काफी शक्तिशाली होते हैं। इस नस्ल के नर का औसतन भार 450 किलो और गाय का औसतन भार 360 किलो होता है। इसके दूध की वसा 4.2 प्रतिशत होती है। यह एक ब्यांत में औसतन 240-515 किलो दूध देती है।

छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिला कृषि का दर्जा

राज्य के 50 हजार किसानों को होगा फायदा

संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती करने वाले किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है। राज्य शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत कुसुम, पलाश, बेर आदि वृक्षों तथा सेमियालता आदि फसलों पर लाख उत्पादन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए कृषकों अथवा कृषक समूहों को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण निर्धारित ऋणमान पर प्रदान किया जाएगा। इसमें लाख उत्पादक तथा प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए कृषक अथवा कृषक समूहों को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण पर नियमानुसार ब्याज अनुदान देय होगा। इस आशय का आदेश विगत दिवस मंत्रालय महानदी भवन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

किसानों को फायदा

राज्य सरकार द्वारा कृषकों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से छत्तीसगढ़ में लगभग 50 हजार किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वर्तमान में राज्य में 4500 टन लाख का उत्पादन होता है। राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासी तथा वनवासी कृषक इसकी खेती में लगे हुए है और यहां लाख की खेती की अच्छी संभावनाएं भी है। राज्य सरकार के इस निर्णय के तहत किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण जैसी सुविधा के मिलने से लाख की खेती तथा इसके उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य में लाख का उत्पादन बढ़कर 10 हजार टन तक हो जाएगा।

गेहूं के भूसे से बनाया नया नष्ट होने वाला पोलीयूरीथेन फोम

नई दिल्ली, एजेंसी

दुनिया भर में हर साल लगभग 73.4 करोड़ टन गेहूं के भूसे या पराली का उत्पादन किया जाता है, जो बड़ी मात्रा में कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है, या जला दिया जाता है। गेहूं का यह भूसा सस्ता है और अब तक इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। हाल ही में स्पेन के कॉर्डोबा विश्वविद्यालय में आरएनएम केमिकल इंजीनियरिंग और एफक्यूएम नानोवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च ग्रुप्स ने पॉलीयूरीथेन फोम बनाने में गेहूं के भूसे का उपयोग करने में सफलता प्राप्त की है। पॉलीयुरेथेन एक पॉलिमर है जो कार्बामेट लिंक से जुड़ने वाली कार्बनिक इकाइयों से बना है। पोलीयूरीथेन फोम रबर के रूप में भी जाना जाता है, यह प्लास्टिक सामग्री, जिसे अक्सर पेट्रोलियम सह-उत्पादों से निर्मित किया जाता है, उद्योग के लिए बहुत आवश्यक

है और इसका उपयोग निर्माण और ऑटो मोबाइल क्षेत्रों में सीलेंट के साथ-साथ कई तरह के सामान बनाने तथा एक थर्मल और ध्वनिक इन्सुलेटर बनाने के लिए किया जा सकता है।

एक नया प्रयोग

चिली के एडवांस्ड पॉलिमर रिसर्च सेंटर (सीआईपीए) ने इसको बनाने में अहम भूमिका निभाई है। शोधकर्ताओं ने गेहूं के कचरे से एक नया प्रयोग किया है। कचरे को तरल में बदला जाता है, जिससे पॉलीओल्स प्राप्त किए जाते हैं। ये पॉलीओल्स उन प्रमुख यौगिकों में से एक हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं जो पोलीयूरीथेन फोम बनाते हैं।

चर्चा में आया शोध

आज तक अरंडी का तेल टिकाऊ पोलीयूरीथेन फोम प्राप्त करने की दौड़ में प्रमुख में से एक रहा है जिसे पेट्रोलियम की आवश्यकता नहीं होती है। शोधकर्ता एस्तेर रिनकॉन द्वारा बताया गया कि यह वनस्पति तेल के हवा के संपर्क में आने से यह पूरी तरह से कठोर और सूखता नहीं है जो कि रबर फोम बनाने की उचित प्रक्रिया में से एक है। यह शोध पॉलिमर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

कम कर दिया उपयोग

नए शोध ने गेहूं के भूसे ने अरंडी के तेल के 50 फीसदी तक के उपयोग को कम कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सामान पारंपरिक तरीकों से बनाया गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि हम बहुत ही कम से कम मापदंडों का उपयोग कर इसे प्राप्त करने में सक्षम रहे। एस्तेर रिनकॉन बताते हैं कि फोम के निर्माण में, गेहूं के भूसे को 96 फीसदी तक को परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा, जैसा कि शोधकर्ता ने बताया है, उन्होंने वर्तमान में बाजार पर मौजूद उत्पादों की तुलना में आसानी से नष्ट होने वाले का उपयोग किया हैं, जिसका अर्थ है कि इससे बनी सामग्री आसानी से विघटित/नष्ट होने में कम समय लगता है।

पद्मश्री बाबू लाल दाहिया ने कहाः हरित क्रांति ने देश में खेती का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया

धान और दूसरे परंपरागत बीजों बचाने की जरूरत

बाबूलाल दाहिया

लोक साहित्य में रचे-बसे पद्मश्री बाबूलाल दाहिया खुद नहीं जानते थे कि वो आगे चलकर परम्परागत धान की लगभग 200 किस्मों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। आज उनके पास कोदो, कुटकी सहित अन्य तरह के बीजों के किस्में भी हैं जिन्हें उन्होंने संरक्षित किया है। विंध्य में बघेली कविताओं के शीर्षस्थ कवि रहे बाबूलाल दाहिया ने अपना पूरा जीवन परंपरागत बीजों को बचाने और देश दुनिया को यह समझाने में खपा दिया कि लौटना हमें जड़ों की ओर ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि उनका यह प्रयास कम पड़ रहा है। उनका मानना है कि सरकार खेती और किसानों को बचाने के लिए जो भी कर रही है वह नाकाफी है। पेश है 'जागत गांव हमार' के लिए दीपक गौतम से उनकी बातचीत के प्रमुख अंश-

सवालः आपको इस काम के लिए प्रेरणा कहां से मिली और कैसे आप तो इस काम को देखते है?

जवाबः मैं तो लोक साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी हूं। साथ में खेती किसानी का काम भी करता हूं। खेतों में काम करत-करते मैंने देखा कि हमारे पहले से धान की बहुत सारी किस्में थीं, जिनमें से बहुत सारी समाप्त हो गईं और कुछ हैं भी तो समाप्त होने की कगार पर हैं। मुझे लगा कि मुझे लोक साहित्य के साथ-साथ धान और दूसरे परंपरागत जो अन्य फसलों बीज हैं उन्हें बचाने की जरूरत है और उनके लिए काम करना चाहिए, तो मेरा रुझान इस काम के प्रति बढ़ता चला गया और धीरे-धीरे मैं काम करने लगा। काम करते-करते मैंने आज धान की 230 परंपरागत किस्मों को बचाल लिया है।

सवालः क्या आज के दौर में खेती किसानों की आय के लिए एक बेहतर विकल्प है?

जवाबः देखिए खेती का विकल्प या परंपरागत खेती का विकल्प तो कुछ नहीं है। जिस तरह से लोक साहित्य हमारे जीवन में रचा बसा हुआ है, परंपरागत बीज भी ठीक वैसे ही हैं कि इन्हें इस मौसम की और पारिस्थितिकी की इस पूरे तंत्र की आदत है। वह यहीं पैदा हुए हैं, यहां की प्रकृति और वह गर्मी, धूप वर्षा सब कुछ सहने के आदी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। हमारी जो परंपरागत फसलें हैं उन्हें सहेजने की जरूरत हैं। ये फसलें हमारे स्वास्थ्य और मौसम के भी अनुकूल है। 200 तरह की किस्में या 200 के बीज, जिन्हें हम किसानों के फायदे के लिए बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य कितना प्रभावित हो रहा है। अगर आपने कोई एक किस्म दे दी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काम करे, जो शरीर पर लगे तो मुझे लगता है कि वह सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा।

सवालः खेती जैविक खेती फायदेमंद नहीं है तो फिर आप और क्या देखते हैं?

जवाबः मैं मानता हूं कि इस देश में खेती का पूरा स्ट्रक्चर हरित क्रांति आने के बाद से धीरे-धीरे बदल गया। हम और हमारे किसान पहले जिस तरह की व्यवस्था में थे उस व्यवस्था में हमारा पशुधन हमारे किसानों के लिए सबसे काम की चीज थी। वह बहुत कारगर था और पशुधन से एक किसान न केवल दूध और इस तरह के फायदे ले पाता था, बल्कि उसे खेती में भी पूरी मदद मिलती थी। आज हमारे पास उपकरण हैं, बाकी तमाम तरह की चीजें हैं, खेती में इतने सारे बदलाव हो गए हैं, यदि हम कहें कि हरित क्रांति के बाद से तरह-तरह के खाद और बीज मिलने लगे हैं और जिन्हें किसान लगातार प्रयोग कर रहा है, उनसे पैदावार तो बए रही है, लेकिन इन आधुनिक प्रयोगों ने देश की जमीनों को बर्बाद करके रख दिया। और हो भी क्क्यों न, क्योंकि हमें तो अब सिर्फ 2 गुना 4 गुना 10 गुना उत्पादन चाहिए, जमीन अच्छी रहे या खराब हो जाए इससे हमें कोई लेना देना नहीं रह गया है। पहले तो हम भुखमरी से जूझ रहे थे और उससे निपटने के लिए हम कुछ भी करते गए। हमें अब महसूस हो रहा है कि हमनें उत्पादन बढ़ाने के लिए जो नए-नए प्रयोग किए उससे हमारी समस्याएं बढ़ीं हैं कम नहीं हुई। हमारा अंध प्रयास हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। पहले लोगों को कैंसर और तमाम बाकी तरह के जो अभी रोग हो रहे हैं कहीं से कहीं तक लोगों के अंदर नहीं था। लोग इसी धरती में रहते थे इसी धरती से उपजा खाते थे और उसी धरती में चादर तान के सो भी जाते थे। मैं तो मानता हूं कि सरकार में किसान को समझने वाले लोग हैं खेती को समझने वाले लोग सारे के सारे लोग या तो व्यापारी हैं या बने हुए किसान हैं या बनिया। मेरा यही मानना है कि हरित क्रांति से लाभ नहीं हुआ, यह एक अभिशाप की तरह है।

सवालः आपने बड़े-बड़े मंचों पर अपनी बात रखी होगी तो उनका क्या उत्तर मिलता है?

जवाबः देखिए अभी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के साथ वार्ता से जुड़ा हुआ था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने जैसे ही उन्हें परंपरागत खेती और तमाम तरह की दूसरी चीजों के बारे में बताया। सरकार किसानों की आय दोगुना नहीं कर सकती है, क्योंकि किसानों की आय दोगुना करने का जो व्यावहारिक तरीका है वह सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं। आप यह बताइए पुराने 20 साल पहले की बात करते हैं, 20 साल पहले और इस समय में रुपए का मूल्य मैं मानता हूं 10 गुना घट गया है। इसका आकलन करना चाहिए आप ऐसे कर सकते हैं। इस देश में जो भी नियम कानून कायदे बनाए गए वह किसानों के हितैषी साबित नहीं हुए। सरकारों ने अपना उल्लू सीधा किया है और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है।

सवालःयदि आप इस तरीकों को ठीक नहीं मानते हैं तो इसमें किस तरह के सुधार की जरूर है?

जवाबः जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इसमें सरकारों को या प्रशासन में बैठे लोगों को किसानों से जमीन पर आकर बातचीत करनी चाहिए, जमीन पर देखना चाहिए किसान कहां किस तरह की मुसीबत में हैं और उनके लिए जरूरी क्या है। आज बहुत सारी वैकल्पिक कृषि है दूसरी तरह की कृषि है फल-फूल औषधि और तमाम तरह की चीजें इन सब से जुड़ा भी कुछ हो सकता है, पर सबसे बड़ी जरूरत मुझे लगता है कि सरकार को किसानों से बातचीत करने की है।

देश में आयातित कृषि उत्पादों की खेती को बढ़ावा देने की जरूरतः आईसीएआर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि शोध संस्थान आईसीएआर से किसानों की आय बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन कृषि उत्पादों की खेती करने को कहा जिनका फिलहाल आयात हो रहा है। आईसीएआर को आयातित खाद्य पदार्थों का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के साथ गठजोड़ करना चाहिए। देश हर साल 230 करोड़ रुपए का फूलों का आयात करता है जबकि 5,000 करोड़ का फलों का आयात होता है। इन कृषि, बागवानी और फूलों की खेती को देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आईसीएआर का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और नवप्रवर्तन है और ये दोनों देश के किसानों और उनके भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिये उन्हें स्टार्टअप से जोड़ने के उपायों पर काम करना चाहिए। इससे किसानों को नए विचार मिलेंगे। ई-वाणिज्य का उपयोग कृषि उत्पादों के निर्यात में किया जा सकता है।

अन्नदाताओं को फसल का अधिक दाम मिलेगा

गेहूं से पहले होगी चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में गेहूं से पहले समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी की जाएगी। इससे मंडी में चना की उपज का भाव बढ़ेगा, जिससे किसानों को अधिक फसल का दाम मिल सकेगा। इसकी तैयारी की जा रही हैं। रबी सीजन में गेहूं और चना की फसल पहले पकती है, लेकिन समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी बाद में होती है। ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य से कम भाव पर मंडी में चना की उपज बेचनी पड़ती है, जबकि समर्थन मूल्य पर चना की फसल की खरीदी पहले शुरू होने पर मंडी में जरुरतमंद व्यापारी भाव बढ़ाकर चना खरीदेंगे। इसका फायदा किसानों को मिलेगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन चल रहा है। हर साल समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पहले शुरू होती है, जबकि पहले फसल चना की पकती है। इसके कारण छोटे किसान चना की फसल कम दाम पर मंडी में व्यापारियों को बेचने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इस बाद ऐसा नहीं होगा।

इनका कहना है

चना की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी पहले शुरू होगी। इसकी तारीख बैठक में तय की जाएगी। पिछले साल समर्थन मूल्य मूंग की खरीदी की घोषणा होने के बाद ही मंडी में व्यापारियों ने मूंग के भाव बढ़ाकर खरीदी की, इससे के किसानों को फायदा हुआ।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
रायसेन, बृजेश ठाकुर-9926777555
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
गंजबासौदा, प्रदीप श्रीवास्तव- 7987780456
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति -9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

मध्यप्रदेश शासन

आइये, इस गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों की सहभागिता की सुदृढ़ बुनियाद पर हम ऐसे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लें, जो देश में समानता, सद्भाव और सबसे तेज प्रगति की मिसाल बने।

देश के लिए बलिदान होने वाले वीर सपूतों को शत्-शत् नमन।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

आत्मनिर्भर हों जन-जन नवचेतना नवऊर्जा का

गणतंत्र

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

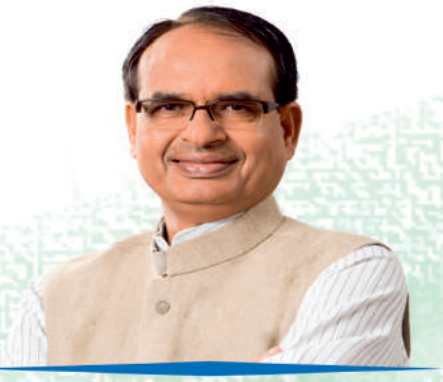

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

खुशहाल जीवन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम...

- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जारी। यह पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य। नीति आयोग ने की इस पहल की प्रशंसा।
- मनरेगा योजना में अब तक 86 लाख 37 हजार मजदूरों को रोज़गार, इनमें 36 लाख 87 हजार महिलाएं। प्रतिदिन लगभग 20 लाख श्रमिकों का नियोजन। देशभर में सर्वाधिक।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम।
- कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का "मोस्ट इम्प्रूव्ड" राज्य।
- सुशासन को मूर्तरूप देने के लिए एकल नागरिक डेटाबेस।
- कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू।
- मिलावटखोरी अब संज्ञेय अपराध।
- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना शुरू, 21 राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों पर राशन उपलब्ध।
- 781 करोड़ की अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना का क्रियान्वयन।
- प्रदेश के इतिहास में 2789.55 लाख यूनिट बिजली सप्लाई का नया रिकार्ड।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन कैबिनेट का गठन।
- ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य (Historical Urban Landscape) की ग्लोबल रिकमेन्डेशन योजना के तहत चयनित।
- शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में स्मारक निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर।
- धार्मिक स्वातंत्र्य अब बना कानून।

D-18185/2020

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2021

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)